RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 29 JANUARY TO 04 FEBRUARY 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 23 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

अवीवा इंडिया ने नील करिया को चीफ फाईनेंशल ऑफिसर नियुक्त किया
Page 3

एलपीजी वाहनों पर जीएसटी घटाये सरकार: उद्योग संगठन
Page 4

कोरोना वायरस: ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने की बड़ी खोज, जल्द मिल सकता है इलाज
Page 7

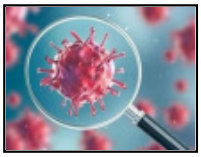

editoria!

लोकलुभावन बजट की उम्मीद

भारतीय उद्योग जगत के मुख्य कार्याधिकारियों को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था की सुस्त पड़ती रफ्तार को गति देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को पेश होने वाले आम बजट में आयकर में कटौती, ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने और रोजगार सृजन के उपायों की घोषणा कर सकती हैं। कंपनी जगत की राय जानने के लिए इस हफ्ते देश भर में 25 मुख्य कार्याधिकारियों के बीच सर्वेक्षण कराया गया। इनमें से अधिकांश ने उम्मीद जताई कि बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के उपायों की घोषणा की जा सकती हैं।

सर्वेक्षण में शामिल 56 फीसदी मुख्य कार्याधिकारियों ने कहा कि वे 'लोकलुभावन' बजट की उम्मीद कर रहे हैं जिससे उपभोग मांग को बढ़ावा मिलेगा। अधिकांश मुख्य कार्याधिकारियों (88 फीसदी) ने उम्मीद जताई कि सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने जैसे कदम उटाएगी। दिल्ली की एक कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा, 'सरकार को आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए ग्रामीण मांग में सुधार लाने के उपाय निश्चित तौर पर करने चाहिए।' सर्वेक्षण में शामिल करीब आधे प्रतिभागियों का कहना था कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के लक्ष्य को कम करने की उम्मीद नहीं है, वहीं 24 फीसदी प्रतिभागियों ने इसे और घटाए जाने की बात कही।

करीब 80 फीसदी मुख्य कार्याधिकारियों ने उम्मीद जताई कि सरकार उपभोक्ता व्यय को बढ़ावा देने के लिए आयकर दरों में कटौती कर सकती है। हाल के महीनों में ऐसा देखा गया है कि ग्राहक नई कार या मकान नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने भविष्य की चिंता है। मुख्य कार्याधिकारियों ने कहा कि आयकर दर में कटौती से करदाताओं के हाथों में अतिरिक्त पैसा बचेगा जिससे उपभोक्ता व्यय में सुधार लाने में मदद मिलेगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। हालांकि 56 फीसदी मुख्य कार्याधिकारियों ने उम्मीद जताई कि धनाढ्यों पर ज्यादा कर लगाया जा सकता है।

सर्वेक्षण में शामिल करीब 84 फीसदी मुख्य कार्याधिकारियों ने कहा कि उन्हें शनिवार को पेश होने वाले बजट में रोजगार सृजन के लिए कई घोषणाएं किए जाने की उम्मीद है। कोलकाता की एक कंपनी के सीईओ ने कहा, 'अगर भारत को 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल करना है तो इसमें रोजगार सृजन पर ज्यादा जोर देना होगा।' जब उनसे पूछा गया कि क्या वे उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री राजकोषीय घाटे के बारे में पारदर्शी आंकड़े देंगी, तो करीब आधे सीईओ (48 फीसदी) ने इसका नकारात्मक जवाब दिया जबकि 32 फीसदी को भरोसा था कि इस मामले में सीतारमण पारदर्शी रुख अपनाएंगी। मुख्य कार्याधिकारियों को उम्मीद है कि विदेशी निवेशकों की धारणा को मजबूत करने के लिए बजट में कई घोषणाएं की जाएंगी। विदेशी निवेशक निवेश फैसलों के लिए बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तीन-चौथाई सीईओ का मानना है कि बजट में विदेशी निवेशकों के लिए कई आकर्षक घोषणाएं की जाएंगी। एक स्टील कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा, 'विदेशी निवेशक और ज्यादा की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें कई तरह की आशंकाएं हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। साथ ही भारतीय न्याय व्यवस्था भी बहुत धीमी है।' दक्षिण अफ्रीका की कंपनी बिडवेस्ट ने इस महीने सरकार को पत्र लिखकर मुंबई हवाई अड्डे में अपनी हिस्सेदारी बेचने में मदद मांगी है। मुकदमेबाजी के कारण वह पिछले एक साल से अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच पा रही है। उच्चतम न्यायालय के दूरसंचार कंपनियों को सरकार की मांग के मुताबिक समायोजित सकल राजस्व भुगतान करने का आदेश देने से भी विदेशी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है। वित्तीय संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया में बहुलांश हिस्सेदारी वाली वोडफोन पीएलसी के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा कि भारी खर्च के कारण उसकी भारतीय इकाई पर परिसमापन का खतरा मंडरा रहा है।

पेट्रोल-डीजल हो सकते हैं महंगे

नई दिल्ली। एजेंसी

तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक की ओर से कच्चे तेल की सप्लाई में कटौती करने की उम्मीदों से मंगलवार को तेल के दाम में वापस तेजी आ गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में एक फीसदी से ज्यादा की तेजी आई जबकि घरेलू वायदा बाजार में कच्चे तेल के दाम में डेढ़ फीसदी से ज्यादा का उछाल आया। जानकार बताते हैं कि ध्ध्ंि अगर कच्चे तेल की आपूर्ति में कटौती करता है तो आने वाले दिनों में दाम में फिर तेजी का रुख बना रहेगा जिससे भारत में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम में उपभोक्ताओं को जो राहत मिल रही थी, उस पर ब्रेक लग जाएगा।

कच्चे तेल की कीमत में उछाल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर रात 9.29 बजे कच्चे तेल के फरवरी अनुबंध में पिछले सत्र के मुकाबले 63 रुपये यानी 1.67 फीसदी की तेजी के साथ 3,846 रुपये प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था जबकि आरंभिक सत्र के दौरान कच्चे तेल का भाव 3,763 रुपये प्रति बैरल तक लुढ़का था। वहीं, इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड के अप्रैल अनुबंध में पिछले सत्र के मुकाबले 0.67 फीसदी की तेजी के साथ 58.97 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था जबकि कारोबार के दौरान ब्रेंट क्रूड का भाव 59.34 डॉलर प्रति बैरल तक उछला।

OPEC के संकेत से दाम में इजाफा

वहीं, न्यूयॉर्क मर्के टाइल एक्सचेंज (नायमैक्स) पर अमेरिकी लाइट क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) के मार्च अनुबंध में पिछले सत्र के मुकाबले 0.72 फीसदी की तेजी के साथ 53.52 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था, जबकि कारोबार के दौरान डब्ल्यूटीआई का भाव 53.91 डॉलर प्रति बैरल तक उछला। कमोडिटी बाजार विशेषज्ञों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम को थामने के मद्देनजर ओपेक कच्चे तेल की आपूर्ति में कटौती करने पर विचार कर रहा है। यही कारण है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण तेल की मांग में नरमी के मद्देनजर जो दाम पर दबाव देखा जा रहा था, वह कम हो गया है।

बढ़ती आर्थिक मंदी और बेरोज़गारी के चलते

सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध से दो कदम पीछे हटी सरकार

नई दिल्ली। एजेंसी

सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधन करने के मामले में केंद्र सरकार ने दो कदम फिलहाल पीछे खींच लिया है। इसके पीछे प्रमुख कारण देश में बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक मंदी है। इसके चलते सरकार अभी प्लास्टिक उद्योग पर सीधे प्रतिबंध लगाने से बच रही है। सरकार इस मामले में ठोस कदम उठाने के लिए चर्चा ज़रुर कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी रुप रेखा बनकर तैयार नहीं हुई है। सरकार ने तय किया है कि 2022 तक सिंगल प्लास्टिक यूज़ को खत्म करेंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरकार अपने हाथ को पीछे खींच लिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक सूत्र के अनुसार, 'बिना सोचे समझे कोई फैसला लेते हैं तो रोज़गार प्रभावित होंगे। जिसका कहीं न कहीं इकोनॉमी पर असर देखने को मिलेगा. जो मानक तय किए गए थे उसके अनुरुप सुनियोजित तरीके से कैसे बैन करे इस विचार चल रहा है।

एक अन्य सूत्र के अनुसार, 'सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बैन होने के बाद विकल्प क्या होंगे इस पर मंथन चल रहा है। जो आसानी से सभी के लिए फायदेमंद हो. इसके चलते देरी हो रही है। फिलहाल जल्दबाज़ी में लिया निर्णय लोगों के रोज़गार पर प्रभाव डाल सकता है। सरकार की घोषणा के बाद कुछ राज्यों ने इसे प्रतिबंध भी किया है, लेकिन सरकार अब एक पॉलिसी पर काम कर रही है।'

दो बैठकों में सुझाव मांगे, फिर कुछ नहीं हुआ

ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में एसोसिएशन की पर्यावरण समिति के सदस्य हितेन भेड़ा ने कहा, 'फिलहाल कुछ राज्य अपने स्तर पर ही प्रतिबंध लगाने को लेकर काम कर रहे हैं। फिलहाल केंद्र से कुछ नहीं हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी निर्देश दिए है कि राज्य अपने स्तर पर कुछ कार्रवाई करे। इसके कारण राज्य कुछ छोटे-मोटे कदम उठा रहे हैं।'

भेड़ा के अनुसार, 'पहले से अभी की तुलना में प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर चल रही मुहिम ठंडी पड़ गई है। गांधी जयंती के पहले कई बैठकों के दौर चले, लेकिन उसके बाद से अभी तक केवल एक या दो ही बैठकें हुई हैं। एक बैठक में प्लास्टिक को रिसाईकल कैसे करें इस पर भी चर्चा हुई थी। जिसमें हमने सभी लोगों ने कुछ सुझाव दिए थे। इस दौरान हमने प्लास्टिक प्रतिबंध को लेकर एक नीति लाने की मांग भी की थी। भेड़ा ने कहा, 'यह इतना जटिल विषय है कि सभी कारणों को ध्यान में रखकर सोच विचार किया जा रहा है, इसके चलते समय लग रहा है।' भेड़ा के मुताबिक, 'सरकार यह नहीं तय कर पा रही है कि कौन-कौन से आयटम पर उन्हें बैन लगाना है। सरकार बिना कुछ सोचे समझे कदम उठाती है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इससे पांच से छह लाख लोगों के रोज़गार पर संकट होगा। इसका असर आर्थिक परिदृश्य पर नज़र आएगा।'

(शेष पृष्ठ 2 पर)

भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन 2019 में 1.8 प्रतिशत बढ़कर 11.12 करोड़ टन रहा: रिपोर्ट

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश में कच्चे इस्पात का उत्पादन 2019 में मामूली 1.8 प्रतिशत बढ़कर 11.12 करोड़ टन रहा। स्टील उत्पादकों का संगठन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने यह जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार देश में कच्चे इस्पात का उत्पादन 2018 में 10.93 करोड़ टन था। इसमें कहा गया है, ''भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन 2019 में 11.12 करोड़ टन रहा जो 2018 के मुकाबले 1.8 प्रतिशत अधिक है।'' वहीं वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात का उत्पादन 2019 में 186.99 करोड़ टन था जो 2018 के मुकाबले 3.4 प्रतिशत अधिक है। पुनः रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल एशिया और पश्चिम एशिया को छोड़कर दुनिया के हर क्षेत्रों में कच्चे इस्पात का उत्पादन घटा है। चीन में उत्पादन आलोच्य वर्ष में 8.3 प्रतिशत बढ़कर 99.63 करोड़ टन रहा। वैश्विक उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी पिछले साल बढ़कर 53.3 प्रतिशत हो गयी जो इससे पूर्व 2018 में 50.9 प्रतिशत थी। जापान में कच्चे इस्पात का उत्पादन आलोच्य वर्ष में 9.93 करोड़ टन रहा जो 2018 के मुकाबले 4.8 प्रतिशत कम है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया में उत्पादन 2019 में 7.14 करोड़ टन रहा जो इससे पूर्व वर्ष के मुकाबले 1.4 प्रतिशत कम है।

हाजिर मांग और वैश्विक संकेतों से कच्चा तेल वायदा भाव में तेजी

नयी दिल्ली। सकारात्मक वैश्विक रुख के बीच सटोरियों ने ताजा सौदों की लिवाली की जिससे बुधवार को वायदा कारोबार में कच्चातेल की कीमत 48 रुपये की तेजी के साथ 3,856 रुपये प्रति बैरल हो गई। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा अपने सौदों का आकार बढ़ाने के कारण यहां वायदा कारोबार में कच्चातेल कीमतों में तेजी रही। एमसीएक्स में कच्चातेल के फरवरी डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 48 रुपये अथवा 1.26 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,856 रुपये प्रति बैरल हो गई जिसमें 24,104 लॉट के लिए कारोबार हुआ। कच्चातेल के मार्च डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 44 रुपये अथवा 1.15 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,874 रुपये प्रति बैरल हो गई जिसमें 736 लॉट के लिए कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर, वेस्ट टैक्सास इंटरमीडिएट की कीमत 1.08 प्रतिशत की तेजी के साथ 54.06 डॉलर प्रति बैरल हो गयी। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मानक माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.13 प्रतिशत की तेजी के साथ 60.18 डॉलर प्रति बैरल हो गयी।

रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़क बनाने की प्रौद्योगकी सौंपने की पेशकश

नागोथाने -महाराष्ट्र। एजेंसी

उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएसएआई) को अपनी 'प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़क' निर्माण की प्रौद्योगिकी देने की पेशकश की है। इस प्रौद्योगिकी से सड़क निर्माण में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी ने रायगढ़ जिले स्थित अपने नागोथाने विनिर्माण संयंत्र में इस प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया है। इसके अलावा वह कई और पायलट परियोजनाओं पर काम कर रही है। कंपनी ने अपने संयंत्र में 50 टन प्लास्टिक अपशिष्ट को कोलतार के साथ मिलाकर करीब 40 किलोमीटर लंबी सड़क बनायी है। कंपनी के पेट्रोरसायन कारोबार के मुख्य परिचालन अधिकारी विपुल शाह ने संवाददाताओं से कहा, '' पैकेटबंद सामानों के खाली पैकेट, पॉलीथीन बैग जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट का इस्तेमाल सड़क निर्माण में करने की प्रणाली विकसित करने में हमें करीब 14 से 18 महीने का वक्त लगा। हम इस अनुभव को साझा करने के लिए एनएचएआई के साथ बाचतचीत कर रहे हैं। ताकि सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग किया जा सके।'' एनएचएआई के अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज देशभर में राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को भी यह प्रौद्योगिकी सौंपने के लिए बातचीत कर रही है। कंपनी की यह प्रौद्योगिकी ऐसे प्लास्टिक अपशिष्ट के लिए विकसित की गयी है जिसका पुनर्चक्रण संभव नहीं है। इस अपशिष्ट के सड़क निर्माण में उपयोग से होने वाले लाभ के बारे में शाह ने कहा, ''यह ना सिर्फ प्लास्टिक के सतत उपयोग को सुनिश्चित करेगा, बल्कि वित्तीय तौर पर लागत प्रभावी भी होगा।'' उन्होंने कहा कि हमारा अनुभव बताता है कि इस प्रौद्योगिकी से एक किलोमीटर लंबी सड़क बिछाने में एक टन प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग होता है। इससे हमें एक लाख रुपये बचाने में मदद मिलती है और इस तरह हमने 40 लाख रुपये बचाए हैं। सड़क निर्माण में कोलतार के आठ से दस प्रतिशत तक उपयोग के विकल्प के तौर पर हम इस प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं यह सड़क की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। इस प्रौद्योगिकी से सड़क निर्माण में दो महीने का समय लगा। साथ ही इस प्रणाली से बनी सड़क पिछले साल की मानूसनी बारिश में भी खराब नहीं हुई।

ब्राजील ने उद्योगों के लिए खोले द्वार

नई दिल्ली। एजेंसी

ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोलसोनारो ने लैटिन अमेरिकी देश में बुनियादी ढांचे, रेलवे, खनन और ऊर्जा क्षेत्रों में भारत की दिग्गज कंपनियों को निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। बोलसोनारो ने ब्राजील के वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में उद्योग के दिग्गजों को संबोधित करते हुए भारत से ज्यादा निवेश किए जाने की वकालत की। ब्राजील की अर्थव्यवस्था के 2020 में गति पकड? की उम्मीद है और वहां के केंद्रीय बैंक ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। गरीबी उन्मूलन और भ्रष्टाचार के खात्मे का नारा देकर ब्राजील में लोकप्रियता हासिल करने वाले बोलसोनारो देश में बड़े पैमाने पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश की बात कही। उन्होंने खासकर एमेजॉन रेनफॉरेस्ट पर जोर दिया, जो दूर दूर फैली आबादी में मौजूद है। भारत की कंपनियों ने करीब 6 अरब डॉलर निवेश किया है और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी अहम उपस्थिति है। इन कंपनियों में सूचना तकनीक क्षेत्र की दिग्गज जैसे टेक महिंद्रा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रमुख हैं, जिनके करीब 1,400 कर्मचारी हैं। खनन के क्षेत्र में स्टरलाइट पावर ने ब्राजील के 11 राज्यों में 10 पारेषण परियोजनाएं और 34 सबस्टेशन हासिल किए हैं। वहीं विश्व की सबसे बड़ी कॉर्बन ब्लैक प्रोड्यूसर बिड़ला कार्बन ने अक्टूबर 2018 में ब्राजील में अपने परिचालन के 60 साल पूरे किए हैं। दवा, ऊर्जा, इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल उत्पादन क्षेत्र भी भारत के कारोबारियों की दिलचस्पी के प्रमुख क्षेत्र हैं। नीति निर्माताओं का कहना है कि तेल व प्राकृतिक गैस और बॉयोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सप्ताहांत में हुए समझौते से भारत के कारोबारियों के ब्राजील में प्रवेश की अहम संभावना है। बोलसोनारो ने उद्योग जगत के 23 दिग्गजों से मुलाकात की, जिनमें स्टरलाइट पावर, अपोलो हॉस्पिटल, ओयो रूम्स, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जाइडस कैडिला और ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन आफ इंडिया सहित अन्य कंपनियों से जुड़े लोग शामिल रहे।

निर्यात पर ध्यान

बहरहाल भारत को उम्मीद है कि वह ब्राजील के माध्यम से लैटिन अमेरिकी देशों में निर्यात बढ़ा सकता है, जहां पहुंचना मुश्किल है। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार 2022 तक 15 अरब डॉलर हो सकता है। दोनों देश भारत, मरकोसर प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (पीटीए) को विस्तार देने पर काम कर रहे हैं, जिसमें दोनों देश शामिल हैं। बहरहाल 2018-19 में लगातार तीसरे साल ब्राजील को निर्यात बढ़कर 3.8 अरब डॉलर पहुंच गया है। वहीं आयात घटकर 5.4 अरब डॉलर रह गया है, जिसमें एक साल में एक अरब डॉलर की कमी आई है। जुलाई के मध्य में भारत ने ब्राजील से कहा था कि वह नई दिल्ली के साथ पीटीए को लेकर लैटिन अमेरिकी आर्थिक ब्लॉक के देशों के साथ बातचीत में तेजी लाए, जिसमें अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे शामिल हैं। पीटीए पर 2004 में समझौता हुआ था और यह इस महाद्वीप के व्यापक उपभोक्ता बाजार में पहुंचने का एकमात्र साधन है।

सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध से दो कदम पीछे हटी सरकार

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार पहले भारत में तय करे सिंगल यूज प्लास्टिक की परिभाषा

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की स्वाति सिंह सान्याल ने कहा, 'सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं लगाते हुए केवल लोगों से इसे इस्तेमाल न करने की गुज़ारिश की दिशा में ही काम कर रही है। सरकार को भारतीय परिपेक्ष में सिंगल यूज़ प्लास्टिक की एक परिभाषा तैयार करनी होगी।' 'गांधी जयंती के बाद से लेकर अब तक केवल सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंधन को लेकर एक या दो ही बैठके हुई हैं। इसे आगे बढ़ाने को लेकर अभी तक सरकार खुद आगे नहीं बढ़ी है। केवल गाइडलाइन बनाने पर ही काम कर रही है।'

सिंह ने आगे कहा,'सरकार को इस दिशा में भी विचार करना चाहिए कि अगर प्लास्टिक बैन होता है तो इसके विकल्प क्या होंगे, लेकिन इस दिशा में भी कोई काम नहीं होता दिख रहा है। इसके अलावा सरकार को पूरे देश में अगर प्लास्टिक प्रतिबंध होता है तो इसे देशभर में लागू कैसे किया जाएगा, इस दिशा में भी पूरी विस्तृत योजना तैयार करनी होगी।'

सान्याल ने कहा, 'प्लास्टिक की 50 से 60 प्रतिशत इनफार्मेल इंडस्ट्री है। इसमें लाखों को रोज़गार मिलता है। अगर इन्हें बंद किया जाता है तो पूरी तरह से इकोनॉमी पर प्रभाव दिखेगा। वहीं लोगों के जॉब पर भी असर होगा. क्योंकि इसका सीधा जुड़ाव इकोनॉमी से है। सीपीसीबी के प्लास्टिक डिवीज़न की हेड दिव्या सिन्हा से संदेश, ईमेल के माध्यम से बात करने का प्रयास किया लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का जवाब नहीं मिल पाया।

प्लास्टिक बैन के लिए देश में एक नीति लाए सरकार

साहस एनजीओ की दिव्या तिवारी का कहना है कि 'सरकार ने यह ज़रुर कहा है कि 2022 तक वह सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करेगी, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई नीति तैयार नहीं की है। 2 अक्टूबर 2018 के बाद हमें प्लास्टिक को लेकर सरकार क्या कर रही है, इसे लेकर हमें कोई जानकारी भी नहीं दी गई है। अधिकांश प्लास्टिक एफएमसीजी कंपनी से आता है। इसलिए केंद्र सरकार को इसे बैन करने के लिए एक नीति लानी चाहिए। इससे प्लास्टिक पर रोक लग सकेगी।'

एफएमसीजी सेक्टर में बढ़ा है प्लास्टिक का उपयोग

द ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हितेन भेड़ा ने कहा कि देश में अभी फिलहाल 50 हज़ार से अधिक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग औद्योगिक इकाईयां हैं। इस उद्योग में 40 से 50 लाख लोगों को रोज़गार मिल रहा है। इंडस्ट्री चैंबर एसोचैम और ईवाय नामक संस्था की रिपोर्ट पर नज़र डालें तो भारत में 90 लाख टन प्लास्टिक का उपयोग होता है, जिसे इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। जिसमें गुटखे और शैंपू के पाउच, पन्नी, छोटी बोतलें, स्ट्रॉ, गिलास और कटलरी के कई छोटे सामान शामिल हैं और ये वो प्लास्टिक हैं जिसका दोबारा इस्तेमाल नहीं होता और यही प्लास्टिक प्रदूषण का बड़ा कारण है।

एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते ई-कॉमर्स और संगठित रिटेल उद्योग के कारण लगातार प्लास्टिक की मांग बढ़ रही है। यहां हर सामान प्लास्टिक पैकेजिंग में बिकता है। इसके अलावा प्लास्टिक की बढ़ती खपत का बड़ा कारण भारत में लोगों की लाइफ स्टाइल बदलने, आय में बढ़ोत्तरी और बढ़ती जनसंख्या है। वहीं ग्रामीण भारत में टीवी और अन्य माध्यम बढ़ने के कारण प्लास्टिक के साथ साथ पैकेजिंग उद्योगों की मांग लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट पर नज़र डालें तो एफएमसीजी सेक्टर प्लास्टिक उपयोग बढ़ाने वाला क्षेत्र निकलकर सामने आया है. वित्त वर्ष 2019-20 भारत में पैकेजिंग इंडस्ट्री के 5.15 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। देश में सबसे ज़्यादा 35 प्रतिशत पैकेजिंग, इसके बाद निर्माण और बिल्डिंग के क्षेत्र में 23, ट्रांसपोर्ट में 8, इलेक्ट्रॉनिक्स में 8, कृषि में 7 और अन्य क्षेत्रों में 19 प्रतिशत प्लास्टिक का उपयोग होता है। भारत में रोज़ 25 हज़ार मीट्रिक टन से ज़्यादा प्लास्टिक कचरा निकल रहा है। इसमें से 94 प्रतिशत हिस्सा इस तरह के प्लास्टिक का होता है जो आसानी से री-साइकिल हो सकता है। लेकिन 40 प्रतिशत नालियों को जाम करता है. वहीं नदियों को प्रदूषित करता है।

15 अगस्त को यह कहा था पीएम मोदी

73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने भारत को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने की बात कही थी। इस दौरान पीएम ने देश के लोगों और दुकानदारों- व्यापारियों से भी अपील की थी कि वे प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद करें। पीएम ने कहा था कि देश को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने का अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से एक साथ पूरे देश में शुरू किया जाएगा। पीएम की इस घोषणा के बाद रेलवे, एयर इंडिया समेत कई जगह सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक लगाई गई है, पर पूर्ण बैन के अंदेशे से प्लास्टिक उद्योग में खलबली मच गई थी। 2 अक्टूबर 2018 को सरकार पूरी तरह से देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन करने वाली थी लेकिन आर्थिक मंदी, बेरोज़गारी और कोई विकल्प नहीं होने के चलते सरकार ने इसे टाल दिया। सरकार ने फैसला लिया कि वह लोगों को प्लास्टिक यूज़ नहीं करने को लेकर जागरुकता अभियान देशभर में चलाएगी।

अवीवा इंडिया ने नील करिया को चीफ फाईनेंशल ऑफिसर नियुक्त किया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत की सबसे भरोसेमंद प्राईवेट इंश्योरेंस कंपनी, अवीवा लाईफ इंश्योरेंस ने श्री नील करिया को चीफ फाईनेंशल ऑफिसर के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की। वो कंपनी के गुरुग्राम मुख्यालय में काम करेंगे।अपनी भूमिका में नील स्ट्रेटिजक प्लानिंग, ट्रेज़री एवं फाईनेंशल पर फार्मेंस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सम्हालेंगे। वो कंपनी की स्ट्रेटिजक विकास योजनाओं, कस्टमर फोकस मजबूत करने एवं पिछले दो सालों से चली आ रही अवीवा की भारत के सबसे विश्वसनीय प्राईवेट लाईफ इंश्योरेंस ब्रांड की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अवीवा इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ, श्री ट्रेवर बुल ने कहा, ''हमें नील करिया का अवीवा इंडिया परिवार में स्वागत करने की खुशी है। वो एक एनआरआई हैं और फाईनेंशल सर्विसेस के अनेक पक्षों में विस्तृत अनुभव रखते हैं। वो पाँच सालों से ज्यादा समय से अवीवा इंटरनेशनल परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें हमारे मुख्य सिद्धांतों एवं ग्राहकों पर केंद्रण तथा कंपनी के मुख्य कार्यों की गहरी जानकारी है।स्थानीय एक्ज़िक्यूटिव टीम के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति के साथ हमें विश्वास है कि वो कंपनी को विकास के नए आयामों पर ले जाएंगे।'' अवीवा इंडिया के सीएफओ, श्री नील करिया ने कहा, ''मुझे चीफ फाईनेंशल ऑफिसर के रूप में अवीवा इंडिया के साथ नया सफर शुरू करने की खुशी है। फाईनेंशल सेवाओं में मेरी विशेषज्ञता एवं विदेशी शेयर धारकों के साथ अनुभव के चलते मैं नए आयाम तलाशने तथा अगले कुछ सालों में कंपनी को महत्वाकांक्षी विकास के मार्ग ले जाने के लिए उत्साहित हूँ।मुझ पर विश्वास करने एवं मुझे यह जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं मैनेजमेंट एवं बोर्ड का आभारी हूँ।'' अपनी नियुक्ति से पूर्व नील मर्जर्स एवं एक्विज़िशन के सीनियर वाईस प्रेसिडेंट थे, जो अवीवा पीएलसी में चीफ स्ट्रेट्जी एवं एमएंडए ऑफिसर को रिपोर्ट करते थे। 2014 में अवीवा में नियुक्ति से पूर्व नील ने डिलायट में ऑडिट, फाईनेंशल सर्विसेस एवं कार्पोरेट फाईनेंस के क्षेत्र में काम किया और उन्हें फाईनेंशल परफार्मेंस, प्लानिंग एवं आडिट का अनुभव है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स किया है तथा वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स से क्वालिफाईड फाईनेंशल बिज़नेस प्रोफेशनल(बीएफपी) एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट(एसीए)हैं।

GST पोर्टल में दिक्कतों पर केंद्र की खिंचाई, इंफोसिस को नोटिस

नई दिल्ली। एजेंसी

दिल्ली हाई कोर्ट ने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में पेश आ रहीं तकनीकी दिक्कतों, ग्रीवांस रिड्रेसल में सुस्ती और कई फॉर्म अब तक अपलोड नहीं होने पर जहां केंद्र सरकार और जीएसटीएन की खिंचाई की है, वहीं आईटी सपोर्ट मैनेज करने वाली कंपनियों इंफोसिस और टेक महिंद्रा को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई है कि वित्त वर्ष 2018-19 के एनुअल रिटर्न फॉर्म भरने की डेडलाइन दो महीने दूर होने के बावजूद अब तक इन्हें ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराया गया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि असेसीज को शुरुआती दोनों वर्षों के सालाना रिटर्न फॉर्म एकसाथ भरने की सहूलियत मिले।

दिल्ली सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन (STBA) बनाम केंद्र सरकार व अन्य केस में पिछली सुनवाइयों को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कई निर्देशों और सहमतियों के बावजूद उनका आधा-अधूरा पालन ही हुआ है। याचिकाकर्ता की ओर से शिकायत की गई कि जहां वित्त वर्ष 2017-18 के एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में कई विसंगतियां पेश आ रही हैं, वहीं वित्त वर्ष 2018-19 के उएऊँ 9, 9ँ और 9ण अब तक ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। केंद्र की ओर से दलील दी गई कि दूसरे साल के फॉर्म उपलब्ध कराने से पहले यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि असेसी बिना किसी कन्फ्यूजन के पहले 2017-18 की फाइलिंग कर लें। लेकिन बेंच ने दलील खारिज करते हुए आदेश दिया कि दोनों साल के फॉर्म एक साथ ऑनलाइन किए जाएं और असेसीज को आखिरी दिन तक इंतजार न कराया जाए।

एसटीबीए के वकील पुनीत अग्रवाल और एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट संजय शर्मा ने बताया कि कोर्ट के पिछले निर्देश पर जीएसटीएन ने अधिकारियों के फोन नंबर और ईमेल आईटी अपलोड तो किए हैं, लेकिन इसे 'न्यूज एंड अपडेट' सेक्शन के तहत डाला गया है जो अस्थायी हो सकता है। कोर्ट ने जीएसटीएन से इसे होमपेज पर स्थायी रूप से डालने को कहा। हाल में GSTR-3B की फाइलिंग में तकनीकी दिक्कतों खासकर ओटीपी जेनरेट नहीं होने की शिकायत को भी कोर्ट ने गंभीरता से लिया और आईटी सपोर्ट कंपनी इंफोसिस और ग्रीवांस सिस्टम अपग्रेड करने के लिए हायर की गई टेक महिंद्रा को नोटिस जारी करते हुए 20 फरवरी को अगली सुनवाई पर पेश होने को कहा। कोर्ट ने इन शिकायतों को भी गंभीरता से लिया कि ग्रीवांस रिड्रेसल में तेजी नहीं आई है और पोर्टल में जारी होने वाले टिकटों और क्वेरीज की हिस्ट्री मेंटेन नहीं की जाती और कई टिकट बिना सॉल्यूशन के ही बंद कर दिए जाते हैं। कोर्ट ने ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम को चुस्त और इंटरएक्टिव बनाने को कहा है। साथ ही काउंसिल में हुए कई फैसलों और 31 अक्टूबर को कोर्ट रूम में हुई मीटिंग के बाद उठाए गए कदमों का ऑन रिकॉर्ड ब्यौरा भी मांगा है।

इंदौर में आयोजित होगा मध्यप्रदेश का सर्वप्रथम जैविक सम्मेलन एवं प्रदर्शनी आगामी 7-9 फरवरी 2020

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

आज की परिस्तिथियों में रासायनिक खादों, कीट नाशकों से होने वाले दुष्परिणामों को ध्यान रखते हुए, लोगों में जैविक खान पान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, आगामी 7,8,9, फ़रवरी को स्थानीय कृषि महाविद्यालय में परिसर, सेंट पाल स्कूल के निकट, आर्गेनिक एक्सपो-2020 का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से जैविक उत्पादों से जुडी कंपनियां और आंत्रप्योनर हिस्सा लेंगे। आर्गेनिक एक्सपो-2020 में किसानों के लिए एक विशेष फार्मस मार्केट भी होगा, जिसमें किसान अपने खेतो में उत्पादित जैविक वस्तुओं की प्रदर्शनी एवं विक्रय कर सकेंगे। इस तीन दिवसीय आर्गेनिक एक्सपो में जैविक खेती के महत्वपूर्ण विषयों पर संगोष्ठियों और सेमिनार का आयोजन भी किया जाएगा। इस दौरान देश के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों एवं जैविक विशेषज्ञों के द्वारा ट्रेनिंग एवं उद्बोधन दिया जायेगा। इस जैविक मेले के आयोजक पंडित शिवप्रसाद मिश्रा सुगंधीय एवं जैविक फार्म हैं, जो सीएसआईआर- सीमैप से (सम्बंधित सगंधीय एवं जैविक फार्म)अभिप्रमाणित हैं और एरोमा मिशन के अंतर्गत जैविक लेमनग्रास, पामारोजा, तुलसी, खस इत्यादि की खेती कर रहे हैं। इसके साथ इन उत्पादों के तेल का आसवन पद्धति से विक्रय हेतु उत्पाद भी तैयार होते हैं।

वाहनों के कल-पुर्जों पर समान रूप से 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का आग्रह

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वाहन कल-पुर्जे विनिर्माताओं के संगठन एसीएमए ने आगामी बजट में सभी वाहन कलपुर्जों पर समान रूप से 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का आग्रह किया है। एसीएमए के मुताबिक फिलहाल वाहनों के करीब 60 प्रतिशत कल-पुर्जों पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगता है। वहीं उच्च मूल्य के उपकरणों पर 28 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया जाता है। आटोमोटिव कंपोनेन्ट मैनुफैक्चरर्स एसोसएिशन ऑफ इंडिया (एसीएमए) ने सरकार से अनुसंधान एवं विकास और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिये कोष गठित करने का भी अनुरोध किया। एसीएमए के अध्यक्ष दीपक जैन ने एक बयान में कहा, ''नये नियमन और नीति बदलाव के कारण भारत में वाहन उद्योग उल्लेखनीय बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इसके ऊपर आर्थिक नरमी के कारण घरेलू मांग कम हुई है। हमें उम्मीद है कि आगामी बजट में ग्राहक तथा उद्योग दोनों की धारणाओं को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।'' जैन ने कहा, ''हमें उम्मीद है कि सरकार सभी वाहन उपकरणों पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने के लंबे समय से की जा रही मांग पर विचार करेगी। साथ ही अनुसंधान एवं विकास और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिये कदम उठाएगी।'' इस बीच, साइकिल बनाने वाली हीरो साइकिल ने एक बयान में सरकार से साइकिल पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का आग्रह किया है। साथ ही कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना फेम-2 के दायरे में इलेक्ट्रिक साइकिल को भी लाने की मांग की।

बढ़ सकती है बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों की पेंशन

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार सामाजिक सहायता कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर बदलाव करने पर काम कर रही है जिससे वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों की पेंशन बढ़ सकती है। 80 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन 500 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये और 79 साल तक के वृद्धों की पेंशन मौजूदा 200 रुपये से बढ़कर 500 रुपये हो सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के नैशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (NSAP) में प्रस्तावित बदलाव के जरिए पेंशन को महंगाई से जोड़ा जाएगा। लाभार्थियों की पहचान के लिए सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) का इस्तेमाल किया जाएगा।

उन्होंने कहा, 'हम योजना में आमूलचूल परिवर्तन करने पर विचार कर रहे हैं। पेंशन की रकम बढ़ाने, लाभार्थियों की पहचान के लिए एण्ण डेटा की मदद लेने और इन योजनाओं के तहत 100% DBT ट्रांसफर अपनाने के प्रस्तावों पर विचार विमर्श हो रहा है।' एण्ण लिंकेज से मौजूदा सूची में दो करोड़ से ज्यादा लाभार्थी जुड़ेंगे और इस मद में सरकारी खजाने से होने वाला खर्च लगभग दोगुना हो जाएगा।

मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा के लिए NSAP की कई योजनाओं के तहत हर साल 3.1 करोड़ लाभार्थियों पर 9,000 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। फिलहाल लाभार्थियों की पहचान सुरेश तेंडुलकर कमिटी की बताई गरीबी रेखा के हिसाब से की जाती है। पूरी तरह केंद्र सरकार के फंड से चलने वाले NSAP कार्यक्रम में बुजुर्गों के लिए चार पेंशन और अक्षमता सहायता योजनाएं शामिल हैं। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) शामिल है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के 60 साल या अधिक उम्र के लोगों को 79 साल की उम्र तक हर महीने 200 रुपये और उसके बाद 500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) में गरीबी रेखा से नीचे की 40 से 59 साल की विधवा 200 रुपये मासिक पाने की हकदार होती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) के तहत गरीबी रेखा से नीचे के 18 से 59 साल के विकलांग को 200 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना (NFBS) में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में 18 से 64 साल के मुख्य कमाऊ सदस्य की मौत हो जाने पर परिवार को एकमुश्त 10,000 रुपये की सहायता दी जाती है। सरकारी अधिकारी ने कहा कि लाभार्थियों की पहचान एण्ण-2011 के डेटा के आधार पर करने की वजह यह है कि इसका इस्तेमाल दूसरे बेनिफिट्स बांटने में भी होता है और यह भी आसानी से पता चल जाता है कि लाभार्थी किस हद तक और किस श्रेणी के तहत वंचित है। 1951 में देश में 1.98 करोड़ सीनियर सिटिजन थे। 2001 में यह संख्या 7.6 करोड़ थी जो 2011 में 10.38 करोड़ हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि केंद्र और राज्यों को बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन पर दोबारा विचार कर इसे वाजिब बनाना चाहिए क्योंकि यह रकम 2007 में तय की गई थी, जब यह योजना शुरू की गई थी। उसके बाद से इसमें बदलाव नहीं किया गया है।

निकट भविष्य में भारत में आम हो जाएंगी 'कनेक्टेड' कारें : रिपोर्ट

नयी दिल्ली। इलेक्ट्रिक वाहनों की तेजी से बढ़ती स्वीकार्यता के कारण भारतीय बाजार में निकट भविष्य में इंटरनेट से जुड़ी कार (कनेक्टेड कार) बेहद आम हो जाने वाली है। डिलॉयट ने एक रिपोर्ट में यह उम्मीद जाहिर की है। डिलॉयट वैश्विक वाहन बाजार को लेकर सालाना एक रिपोर्ट 'वैश्विक वाहन उपभोक्ता अध्ययन' जारी करती है। इसके हालिया संस्करण के अनुसार, भारतीय बाजार में आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों तथा कनेक्टेड कारों की मांग में तेजी देखने को मिलेगी। रिपोर्ट में कहा गया, ''निकट भविष्य में कनेक्टेड कार भारतीय बाजार में आम हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ने के कारण कनेक्टेड कारों की मांग में भी तेजी आने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों को नजदीकी चार्जिंग स्टेशन का पता लगाने और टेलीमैटिक्स डेटा तक पहुंच बनाने समेत कई अन्य सुविधाओं में कनेक्टेड फीचर से सहुलियत हो सकेगी।'' डिलॉयट ने कहा कि यात्री वाहनों की बिक्री में हालिया गिरावट के बाद भी कनेक्टेड कार की मांग बढ़ी है। इससे पता चलता है कि उन्नत व कनेक्टेड फीचर के लिये उपभोक्ताओं की भुगतान करने की इच्छा पिछले दो साल में सुधरी है। डिलॉयट इंडिया के पार्टनर राजीव सिंह ने कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं की ठीक-ठाक संख्या है, जो अपने कारों में कनेक्टेड फीचर के लिये 50 हजार से एक लाख रुपये तक का अतिरिक्त बोझ उठाने को तैयार हैं।

नकदी रखने की सीमा तय करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। एजेंसी

नकदी आधारित अर्थव्यवस्था को हतोत्साहित करने के अगले चरण में काले धन पर बने विशेष जांच दल (एसआईटी) ने घर में नकदी रखने की सीमा तय करने का प्रस्ताव किया है। एसआईटी ने यह सुझाव भी दिया है कि कानून और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त की गई अघोषित नकदी को भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाए। प्रस्तावित कदम का मकसद अवैध नकदी रखने पर लगाम लगाना और जांच एजेंसियों द्वारा उनकी जांच के दौरान जब्त की गई अघोषित नकदी के कुप्रबंधन के लिए कड़े मानक पेश करना है।

एसआईटी ने कहा है कि यह तथ्य है कि अघोषित संपत्ति नकदी में रखी जाती है, जिसकी पुष्टि कानून के प्रवर्तन वाली एजेंसियों की समय समय पर की गई तमाम कार्रवाइयों के दौरान जब्त की गई नकदी से होती है। दल ने कहा है कि उचित नकदी प्रबंधन तभी सफल हो सकता है, जब नकदी रखने की सीमा तय की जाए। इस समय केंद्रीय जांच एजेंसियां जब्त की गई अघोषित नकदी संबंधित एजेंसी के भारतीय स्टेट बैंक में खोले गए समर्पित खाते में जमा की जाती है। इसमें चालान पर करदाता का स्थायी खाता संख्या (पीएएन) और नाम होता है, जिनके नाम पर वह राशि जमा की जाती है।

यह सिफारिशें सेवानिवृत्त न्यायाधीश और नौकरशाहों से बने एसआईटी ने की है, जिसकी हाल में अहमदाबाद में केंद्रीय एजेंसियों आयकर, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व खुफिया महानिदेशालय के साथ बैठक हुई थी। इसमें पैनल ने नकदी वाली अर्थव्यवस्था और अघोषित नकदी की जब्ती के दौरान रिश्वत की पेशकश जैसी गलत गतिविधियों को लेकर चिंता जताई थी। जानकारी के मुताबिक पैनल ने नोटबंदी के दौरान सामने आई कुछ घटनाओं पर चर्चा की, जिसमें बड़े पैमाने पर नकदी का कुप्रबंधन किया गया और उसे अन्य मदों में लगाया गया। नोटबंदी के बाद के संपूर्ण वित्त वर्ष 2018 में अघोषित नकदी का 67.91 प्रतिशत 2000 रुपये के नोट में था। वित्त वर्ष 2019 में इसका प्रतिशत थोड़ा कम 65.93 रहा।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस सुझाव को लागू किया जाता है तो नकदी में कारोबार करने वाले कारोबारियों और ग्रामीण इलाकों में घर में नकदी रखने वालों पर असर पड़ेगा। साथ ही अगर जब्त की गई नकदी मामले के फैसले के पहले तक सीएफआई में रखी जाती है तो यह खुला मामला होगा। 2017 में सरकार ने नकदी लेन-देन की सीमा 2 लाख रुपये प्रतिदिन तय की थी। बहरहाल नकदी रखने को लेकर कोई सीमा अभी नहीं है। एसआईटी का गठन उन मामलों का खुलासा करने के लिए किया गया था, जिनमें भारतीय बगैर कर भुगतान वाली अपनी राशि विदेशी बैंक खातों में रखते हैं।

सीएफआई की कार्यप्रणाली के बारे में अधिकारी ने कहा कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत गठित किया गया है। इसमें सरकार की प्राप्तियों और उसके व्यय का हिसाब किताब होता है। सरकार द्वारा किए गए हर व्यय को भारत की संचित निधि से किया जाता है। बहरहाल संसद की मंजूरी के बगैर इसमें से धन नहीं निकाला जा सकता है। सरकार के सालाना वित्तीय विवरण में 3 हिस्से होते हैं- सीएफआई, भारत की आकस्मिक निधि और भारत का सार्वजनिक लेखा। इनमें से सीएफआई सबसे अहम घटक है। राज्यों की अपनी संचित निधि होती है।

एलपीजी वाहनों पर जीएसटी घटाये सरकार: उद्योग संगठन

नई दिल्ली। एजेंसी

उद्योग संगठन इंडियन आटो एलपीजी कोलिशन (आईएसी) ने स्वच्छ वाहन ईंधन को बढ़ावा देने के लिये ऑटो एलपीजी के साथ-साथ गैस ईंधन के लिये कन्वर्जन किट पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती की मांग की है। वाहनों में ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग होता है। यह सर्वाधिक स्वच्छ ईंधन में शामिल है जिस पर फिलहाल 18 प्रतिशत की दर से कर लगता है। वहीं ऑटो एलपीजी /सीएनजी कन्वर्जन किट पर यह 28 प्रतिशत है। संगठन ने बयान में कहा कि स्वच्छ ईंधन पर उच्च दर से जीएसटी सरकार के हरित वाहनों को बढ़ावा देने के रुख के विपरीत है।

आईएसी के महानिदेशक सुयश गुप्ता ने कहा, ''हम ऑटो एलपीजी जैसे पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिये नीतियां तैयार करने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ऑटो एलपीजी को दुनिया भर की सरकार बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन भारत में इसको लेकर नीतियां भेदभावपूर्ण है। इस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। इसी प्रकार, ऑटो एलपीजी और सीएनजी कन्वर्जन किट पर सबसे ऊंची कर की 28 प्रतिशत की दर लागू होती है। इसका मतलब है कि या तो यह विलासिता का सामान है या फिर तंबाकू जैसा अहितकर उत्पाद।'' उद्योग संगठन ने कहा कि एलपीजी दुनिया में सर्वाधिक उपयोग होने वाला वैकल्पिक ईंधन है। इसने हवा गुणवत्ता में सुधार की बात साबित की है।

पर्यावरण चिंता के बीच ऑटो एलपीजी की वैश्विक खपत में पिछले 10 साल में 40 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। दक्षिण कोरिया, तुर्की, पोलैंड, जापान, आस्ट्रेलिया, इटली, मेक्सिको और रूस जैसे देशों ने सफलतापूर्वक इस हरित ईंधन को अपनाया है। आईएसी देश में एलपीजी ऑटो को बढ़ावा देने वाली नोडल एजेंसी है। इसके सदस्यों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां, एलपीजी आधारित वाहनों का विपणन करने वाली, किट आपूर्तिकर्ता और उपकरण विनिर्माता शामिल हैं।

सियाम का बीएस-6 वाहनों पर जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत करने का आग्रह

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम ने सोमवार को सरकार से बजट से पहले प्रोत्साहन आधारित कबाड़ नीति लाने और भारत चरण (बीएस)-6 मानक वाले वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) घटाकर 18 प्रतिशत करने का आग्रह किया है।सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (सियाम) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राज्यों द्वारा खरीदी जाने वाली पेट्रोल-डीजल बसों के लिये बजट आबंटन बढ़ाने का भी

सुझाव दिया। सियाम के अध्यक्ष राजन वढ़ेरा ने एक बयान में कहा, ''हमने वित्त मंत्रालय से प्रोत्साहन आधारित कबाड़ नीति की घोषणा पर विचार करने का आग्रह किया है। साथ ही राज्य परिवहन निगमों द्वारा खरीदी जाने वाली पेट्रोल/डीजल बसों के लिये बजट आबंटन बढ़ाने का भी अनुरोध किया है।''उन्होंने यह भी कहा कि बीएस-6 मानकों वाले वाहनों की लागत अधिक होने से मांग प्रभावित हो सकती है।वढ़ेरा ने कहा, ''इसीलिए हम सरकार से बीएस-6 मानक वाले वाहनों पर जीएसटी एक अप्रैल से 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने का आग्रह करते हैं।''एक अप्रैल से कड़े उत्सर्जन मानक वाले बीएस-6 वाहनों की बिक्री होगी। उद्योग के अनुमान के अनुसार बीएस-6 वाहनों की कीमत कम-से-कम 10 प्रतिशत अधिक होगी।

इंश्योरेंस पॉलसी जिसमें कवर होंगे आपके दोस्त भी...जानें सबकुछ

चेन्नई। एजेंसी

बहुत जल्द एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आने वाली है, जिसमें परिवार के साथ-साथ दोस्त भी इंश्योर्ड होंगे। इस पॉलिसी में सभी मेंबर के लिए एक जैसी सुविधा उपलब्ध होगी। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस और कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की तरफ से 'फ्रेंड एश्योरेंस' का प्रस्ताव रखा गया है। इंश्योरेंस रेग्युलेटरी ईईईए ने इसे मंजूरी दे दी है। पायलट बेसिस पर इसे एक फरवरी से छह महीने के लिए लागू किया जाएगा।

5-30 लोग ग्रुप में शामिल हो सकते हैं

जानकारी के मुताबिक, इस इंश्योरेंस पॉलिसी में 5 से 30 लोग तक शामिल हो सकते हैं। पॉलिसी के तहत बिहेवियर- मसलन कितनी बार डॉक्टर से संपर्क किया गया, कितनी बार हेल्थ चेकअप करवाया गया, के आधार पर ग्रुप के स्कोर तय किए जाएंगे। इसी स्कोर के आधार पर किसी ग्रुप का नया प्रीमियम तय किया जाएगा।

ग्रुप स्कोर से प्रीमियम की दर तय होगी

रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से कहा गया कि अगर पूरे साल में कोई क्लेम नहीं किया जाता है तो अगले प्रीमियम पर 15 पर्सेंट की छूट मिलेगी। मैक्स बूपा की तरफ से कहा गया कि अगर किसी ग्रुप का स्कोर अच्छा होता है तो उसे 5-10 पर्सेंट की छूट मिलेगी।

पूर्व में IRDAI ने कॉन्सेप्ट पर रोक लगा दी थी

फ्रेंड इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट यूरोप के कुछ देशों में है। जर्मनी जैसे देशों में इसका जो कॉन्सेप्ट है वह यहां प्रस्तावित कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग है। पूर्व में IRDAI ने इस कॉन्सेप्ट पर रोक लगा दी थी। उसका कहना था कि ग्रुप का निर्माण इस तरह नहीं किया जा सकता है। ग्रुप बनाने के लिए यह जरूरी है कि मेंबर्स के बीच कुछ कॉमन हो।

भारत ने चीन से आयातित रसायन की डंपिंग जांच शुरू की

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत ने औषधि उद्योग में उपयोग होने वाले चीन से आयातित रसायन की कथित डंपिंग की जांच शुरू की है। एक घरेलू कंपनी से मिली शिकायत के बाद यह कदम उठाया गया है। गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि. ने व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के पास आवेदन देकर चीन से आयातित रसायन एनिलाइन की डंपिंग की जांच का आग्रह किया है।

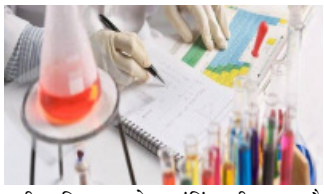

डीजीटीआर की अधिसूचना के अनुसार उसे चीन से आयातित रसायन की डंपिंग के साक्ष्य मिले हैं। उसने कहा, ''प्राधिकरण ने संबंधित उत्पाद के संदर्भ में कथित डंपिंग की मात्रा और प्रभाव का आकलन करने के लिये जांच शुरू की है।'' अगर डंपिंग की बात साबित होती है और यह पता चलता है कि इससे घरेलू कंपनियों को नुकसान हुआ है, महानिदेशालय रसायन के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करेगा। एनिलाइन को एनिलाइन तेल के रूप में जाना जाता है। यह औषधि, डाईज जैसे उद्योग के लिये महत्वपूर्ण है।

गैर- प्रमुख बंदरगाहों पर अप्रैल-दिसंबर में माल ढुलाई 4.8 प्रतिशत बढ़ी

नयी दिल्ली। एजेंसी

देश के गैर प्रमुख बंदरगाहों पर चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में माल ढुलाई 4.8 प्रतिशत बढ़कर 44.72 करोड़ टन पर पहुंच गई। पोत परिवहन मंत्रालय की सोमवार को जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इससे पिछले

वित्त वर्ष की इसी अवधि में गैर प्रमुख बंदरगाहों पर माल ढुलाई 42.65 करोड़ टन रही थी। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल-दिसंबर अवधि के दौरान ओड़िशा के बंदरगाह निदेशालय की माल ढुलाई सबसे अधिक 64.2 प्रतिशत बढ़ी। इस दौरान तमिलनाडु समुद्री बोर्ड बंदरगाह की ढुलाई 34.1 प्रतिशत, बंदरगाह निदेशालय पुडुचेरी की ढुलाई 27.7 प्रतिशत और अंडमान निकोबार द्वीप के बंदरगाह प्रबंधन बोर्ड की ढुलाई 25.4 प्रतिशत बढ़ी। वहीं कर्नाटक के बंदरगाह निदेशालय ने इस दौरान ढुलाई में 25 प्रतिशत और गुजरात समुद्री बोर्ड ने 4.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। वहीं इस दौरान गोवा, केरल समुद्री बोर्ड, महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड तथा आंध्र प्रदेश के बंदरगाह निदेशालय में ढुलाई में गिरावट रिकार्ड की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां तक माल के रखरखाव की बात है तो गुजरात समुद्री बोर्ड में सबसे अधिक 30.49 करोड़ टन माल को चढ़ाने और उतारने का काम हुआ और उसकी हिस्सेदारी 68.2 प्रतिशत रही। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बंदरगाह निदेशालय का नंबर आता है। उसकी बाजार हिस्सेदारी 17 प्रतिशत, महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड की 6.8 प्रतिशत और ओड़िशा के बंदरगाह निदेशालय की हिस्सेदारी 5.7 प्रतिशत रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात समुद्री बोर्ड ने सबसे ज्यादा विदेशी माल का रखरखाव और उतार- चढ़ाव किया। इस बोर्ड में 26.99 करोड़ टन माल का उतार चढ़ाव हुआ जो कि कुल माल के आवागमन में 71.2 प्रतिशत हिस्सेदारी रही। इसके बाद आंध्र प्रदेश बंदरगाह निदेशालय का 16.5 प्रतिशत और ओडिशा बंदरगाह निदेशालय का 6 प्रतिशत हिस्सा रहा।

बजट में बढ़ सकती है भविष्य निधि की पेंशन योजना की न्यूनतम राशि

नयी दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना 'ईपीएस' के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को इस बजट में अच्छी खबर मिल सकती है। योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। क्षेत्र के विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। इसके साथ ही अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का दायरा बढ़ाने और एनपीएस में अतिरिक्त कर छूट की घोषणा भी की जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को 2020-21 का बजट पेश करेंगी। श्रमिक संगठनों का कहना है कि सरकार जब असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों तक के लिये 3,000 रुपये की पेंशन देने का प्रावधान कर सकती है तो फिर संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को इससे कम पेंशन देने का कोई मतलब नहीं है।

श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रजेश उपाध्याय ने इस बारे में 'बातचीत में कहा, ''हमने सरकार को ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक करने का प्रस्ताव दिया है। इस बार के बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाये जाने की घोषणा होने की उम्मीद है।'' कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने को लेकर संघर्ष कर रहे ईपीएस, 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने कहा, ''हमने श्रम मंत्री से मुलाकात कर ईपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर महंगाई भत्ते के साथ 7,500 रुपये मासिक करने की मांग की है।'' उन्होंने यह भी दावा किया कि कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने से सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने इस बारे में श्रम मंत्री को अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपी है।

उल्लेखनीय है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये पीएम श्रम योगी मानधन योजना और छोटे व्यापारियों के लिये प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना चलायी जा रही हैं। दोनों योजनाओं में लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000-3,000 रुपये मासिक पेंशन देने की व्यवस्था है। उधर, पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने भी आगामी बजट में नयी पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में एक लाख रुपये तक के निवेश पर कर छूट देने की सिफारिश की है। अभी व्यक्तिगत करदाताओं को आयकर कानून की धारा 80 सीसीडी (1 बी) के तहत एनपीएस पर 50,000 रुपये तक के निवेश पर अतिरिक्त कर लाभ मिलता है। इसके अलावा पीएफआरडीए ने वित्त मंत्रालय से अटल पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा बढ़ाकर 40 से 60 करने का भी आग्रह किया है। साथ ही मौजूदा अधिकतम पेंशन सीमा 5,000 रुपये को बढ़ाकर 10,000 रुपये मासिक करने का अनुरोध किया है। फिलहाल, अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष के लोग ले सकते हैं।

ताजा सौदों की लिवाली से ग्वारसीड वायदा कीमतों में तेजी

नयी दिल्ली। हाजिर बाजार में मजबूती के रुख के अनुरूप कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को बढ़ाया जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को ग्वारसीड की कीमत आठ रुपये की तेजी के साथ 3,980 रुपये प्रति 10 क्विन्टल हो गयी। एनसीडीईएक्स में ग्वारसीड के फरवरी माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत आठ रुपये अथवा 0.2 प्रतिशत की तेजी के साथ 3,980 रुपये प्रति 10 क्विन्टल हो गयी जिसमें 72,125 लॉट के लिए कारोबार हुआ। इसी प्रकार, ग्वारसीड के मार्च माह में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत छह रुपये की तेजी के साथ 4,024 रुपये प्रति 10 क्विन्टल हो गयी जिसमें 20,595 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार सूत्रों के अनुसार, उत्पादक क्षेत्रों से मामूली आपूर्ति के कारण हाजिर बाजार में मजबूती के रुख को देखते हुए सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को बढ़ाया जिससे ग्वारसीड वायदा कीमतों में तेजी आई।

वसंत पंचमी विशेष

वसंत हमारे द्वार पर खड़ा है। प्रकृति का यह उत्सव हमें प्रकृति से, अपनी परंपराओं, संस्कृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। इस पर्व से कई पौराणिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं। साहित्यकारों ने भी इसकी मनोहारी व्याख्या की है। आइए इस वसंतोत्सव का हृदय से स्वागत करें।

वसंतोत्सव का करें स्वागत

पर्व

नीलम चतुर्वेदी

बनन में बागन में बगरयो बसंत है
कूलन में केलि में कछारन में कुंजन में
क्यारिन में कलिन में कलीन किलकंत है
बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में
बनन में बागन में बगरयो बसंत है...

- कवि पद्माकर

रीतिकालीन कवि पद्माकर को वसंत का कवि कहा जाता है। उनके बाद वसंत की आधुनिक छटा लेकर कविता में अवतरण हुआ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। वसंत पर्व पर जन्मे निराला ने वसंत के अनेक रंग और संदर्भ दिए। एक ओर 'वर दे, वीणावादिनी वर दे' सरस्वती वंदना है, जिसके बिना किसी साहित्यिक-सांगीतिक आयोजन की शुरुआत नहीं होती तो दूसरी ओर 1943 की कविता 'देवी सरस्वती' में किसानी संवेदना इस प्रकार व्यक्त हुई है-

सुख के आंसू दुखी
किसानों की जाया के
भर आए आंखों में/ खेती की माया से
हरी-भरी खेती की सरस्वती लहराई
मग्न किसानों के घर/ उन्मद बजी बधाई

पौराणिक अवधारणा

वसंत उत्सव प्रकृति का सबसे बड़ा उत्सव है। एक ओर प्राकृतिक सौंदर्य है तो दूसरी ओर वाग्देवी मां सरस्वती के अवतरण का शुभ अवसर भी। मदनोत्सव और ज्ञानोत्सव का यह अद्भुत संयोग लोकमानस को भाव-विभोर कर देता है। वसंत से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में वाणी की देवी सरस्वती का इसी अवसर पर अवतरण हुआ। ऋग्वेद के अनुसार देवी सरस्वती का वाहन राजहंस है और वह सफेद कमल पुष्प पर विराजित रहती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ पृथ्वी पर आते हैं और प्रकृति में प्रेम और सौंदर्य का भाव जगाते हैं। इसीलिए सरस्वती पूजन के साथ-साथ इस अवसर पर कामदेव की भी पूजा की जाती है। इस दिन राधा-कृष्ण ने पहली बार एक-दूसरे को गुलाल लगाया था, इसलिए इस अवसर पर गुलाल लगाने की भी प्रथा है।

रुक्मिणी और कृष्ण के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न को कामदेव का प्रतीक माना जाता है, इसी कारण वसंत पंचमी को मदन पंचमी भी कहा जाता है। वसंत पंचमी को ही देवी पार्वती ने कामदेव की मदद से भगवान शिव की योगनिद्रा को भंग करने का प्रयास किया था।

पुराणों के अनुसार श्रीकृष्ण जी ने सरस्वती जी से प्रसन्न होकर, उन्हें वरदान दिया कि वसंत पंचमी के दिन उनकी भी आराधना की जाएगी। माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी से ऋतुओं के राजा वसंत का आरंभ हो जाता है। यह दिन नई ऋतु के आगमन का प्रतीक है।

लोकगीतों में वसंत

इसे ऋतुराज वसंत का प्रथम दिन माना जाता है। लोकगीतों में ऋतुराज का स्वागत ऐसे होता है-

आयो रे ऋतुराज आज ये होरी खेलन आयो
बन बन बाग बाग गलियन में
मधुर सुगंध उड़ायो।।
हरिहर पात, पिछौरी ऊपर अमित रंग ढरकायो।।
आज ये...
बाजत बीन, मृदंग, झांझ, ढ़फ, मंजीरा ठनकायो
गावत फाग औ ढोल बजावत, अति आनंद मनायो।।
आज ये...

सूफी मान्यता

एक प्रसंग सूफियों से भी जुड़ा है। 12वीं शताब्दी में कुछ भारतीय मुस्लिम सूफियों ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर वसंत पर कार्यक्रम मनाने शुरू किए। कहावत है कि अमीर खुसरो ने पीले फूल लेकर पीले वस्त्र पहने कुछ औरतों को पूजा के लिए मंदिर जाते देखा। तभी से वसंत पंचमी को भारतीय सूफियों ने सूफी वसंत के नाम से मनाना शुरू किया।

पारंपरिक मान्यताएं

पारंपरिक रूप से यह त्योहार बच्चों की शिक्षा के लिए काफी शुभ माना जाता है। देश के अनेक भागों में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का श्रीगणेश किया जाता है। बच्चे को प्रथमाक्षर यानी पहला अक्षर लिखना-पढ़ना सिखाया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे विद्यारंभ पर्व कहा जाता है। स्कूलों में सरस्वती पूजा का विशेष आयोजन किया जाता है। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। वसंती रंग समृद्धि, ऊर्जा और सौम्य ऊष्मा का प्रतीक है। भारत में अनेक जगह पतंगबाजी भी की जाती है।

आनंद लें इस पर्व का

इस वर्ष की वसंत पंचमी दस्तक दे रही है। देश वही है, प्रकृति वही है लेकिन उत्सव मनाने वाले कहां खो गए! आज त्योहार इंटरनेट के बधाई संदेश में सिमट गया है। ठहरकर सोचने की जरूरत है। क्या हमारे द्वार तक आया वसंत का न्योता बिना हमसे मिले वापस चला जाएगा? सारी प्रकृति जिस उत्सव के लिए पूरे साल इंतजार करती है, एक बार अपनी बंद दुनिया के दरवाजे खोलकर आइए मिलिए तो! वासंती बयार का स्पर्श महसूस करके तो देखिए।

सरस्वती पूजन का महापर्व

शीत ऋतु की विदाई के साथ माघ शुक्ल पंचमी जहां एक ओर ऋतुराज वसंत के आगमन का सूचक है, वहीं दूसरी ओर संगीत व विद्या की देवी वीणावादिनी मां सरस्वती के अवतरण का दिन भी है। वसंत पंचमी को सभी शुभ कार्यों के लिए अत्यंत उपयुक्त मुहूर्त माना गया है। मुख्यतयाः विद्यारंभ, नवीन विद्या प्राप्ति एवं गृह-प्रवेश के लिए वसंत पंचमी को पुराणों में भी अत्यंत श्रेयस्कर माना गया है।

देवी सरस्वती का अवतरण : सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों समेत मनुष्य की रचना की। लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे, उन्हें लगा कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। भगवान विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा, इसके बाद एक चतुर्भुजी स्त्री के रूप में **अदभुत** शक्ति का प्राकट्य हुआ जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थीं। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव-जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया व पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्माजी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा।

सरस्वती को बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की प्रदाता हैं, संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी कहलाती हैं।

मां की मिलेगी कृपा : सत्वगुण से उत्पन्न होने के कारण इनकी पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां अधिकांशः श्वेत वर्ण की होती हैं जैसे श्वेत चंदन, श्वेत वस्त्र, श्वेत फूल, दही-मक्खन, सफेद तिल का लड्डू, अक्षत, घृत, नारियल और इसका जल, श्रीफल, बेर इत्यादि। इस दिन सुबह स्नानादि के पश्चात श्वेत अथवा पीले वस्त्र धारण कर विधिपूर्वक कलश स्थापना करें। मां सरस्वती के साथ भगवान गणेश, सूर्यदेव, भगवान विष्णु और शिवजी की भी पूजा अर्चना करें। श्वेत फूल-माला के साथ माता को सिंदूर और अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करें।

वसंत पंचमी के दिन माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित करने का विधान है। प्रसाद में मां को पीले रंग की मिठाई या खीर का भोग लगाएं। यथाशक्ति ''ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः'' का जाप करें। मां सरस्वती का बीजमंत्र '' ऐं '' है, जिसके उच्चारण मात्र से ही बुद्धि विकसित होती है। इस दिन से ही बच्चों को विद्या अध्ययन प्रारंभ करवाना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि कुशाग्र होती है और मां की कृपा जीवन में सदैव बनी रहती है।

-अनीता जैन, वास्तुविद

कोरोना वायरसः ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने की बड़ी खोज, जल्द मिल सकता है इलाज

सिडनी। एजेंसी

ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने जानलेवा कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ लड़ाई में बड़ी उपलब्धी मिलने का दावा किया है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने चीन के बाहर एक सैंपल विकसित किया है और इससे जल्द ही कोरोना वायरस का इलाज में ढूंढा जा सकेगा। चीन में कोरोना वायरस का प्रकोप फैला है। सांस से जुड़ी इस बीमारी से अब तक चीन में 132 लोगों की मौत हो चुकी है. करीब 6,000 लोग इससे संक्रमित हैं। मेलबर्न में द डोहर्टी इंस्टिट्यूट (The Doherty Institute) ने बुधवार को बताया कि एक मरीज के सेल कल्चर (जांच) के दौरान कोरोना वायरस का सैंपल विकसित किया गया है। पहली बार चीन के

बाहर विकसित किए गए इस वायरस की डिटेल जल्द ही विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से शेयर की जाएगी। वायरस आइडेंटिफिकेशन लैब के हेड जुलियन ड्रुस ने कहा, 'चीनी अधिकारियों ने इस नोवेल कोरोना वायरस का जीन समूह जारी किया था, जो इस रोग की पहचान करने में मददगार है। हालांकि, असली वायरस होने का मतलब है कि अब जांच की सभी स्तरों का वेरिफिकेशन करने की क्षमता आ गई है, जो इस रोग के इलाज में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। कोरोना वायरस की पहचान और इलाज के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है।' चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि वायरस संक्रमण के 5,974 मामलों की पुष्टि हो गई और वायरस की वजह से होने वाले निमोनिया के 31 नए मामले मंगलवार तक सामने आए थे। सरकारी समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' के अनुसार अभी तक कुल 132 लोग इस वायरस के कारण मारे गए हैं। उसने कहा कि मंगलवार तक हुबेई प्रांत में कोरोना वायरस के कारण 125 लोगों की मौत हो गई और 3,554 मामलों की पुष्टि हुई थी।

होंडा मोटरसाइकिल ने पार किया 25 लाख दुपहिया वाहनों का निर्यात आंकड़ा

नयी दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने कहा कि उसने निर्यात कारोबार शुरू करने के 19 साल बाद 25 लाख दुपहिया वाहनों के निर्यात का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी ने 2001 में एक्टिवा का निर्यात शुरू किया था और 2015 में उसके निर्यात का आंकड़ा 10 लाख के स्तर पर पहुंच गया था। होंडा मोटरसाइकिल वर्तमान में देश से 18 मॉडलों का निर्यात करती है। एचएमएसआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (बिक्री एवं विपणन) यदविंदर सिंह गुलेरिया ने बयान में कहा, 'हमें भारत का अग्रणी स्कूटर निर्यातक बनाने पर गर्व है। साल 2020 में कंपनी की योजना वैश्विक मोटरसाइकिल कारोबार में अपनी स्थिति को मजबूत करने और बीएस-6 वाहनों के युग में निर्यात में वृद्धि पर ध्यान देने की है।' होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया एशिया, पश्चिमी एशिया और लैटिन अमेरिका के 26 देशों में दोपहिया वाहनों का निर्यात करती है।

जरूरत से ज्यादा आपूर्ति की समस्या से गुजर रहा चाय उद्योगः टी बोर्ड अधिकारी

कोलकाता। एजेंसी

घरेलू खपत में सुस्त वृद्धि और निर्यात में नरमी से चाय उद्योग अधिक आपूर्ति की समस्या से गुजर रहा है। टी बोर्ड के उपाध्यक्ष अरुण रे ने न्यूज एजेंसी को बताया, 'चाय उद्योग संकट में है। 2018 की तुलना में 2019 में 5.1 करोड़ किलोग्राम अधिक चाय का उत्पादन हुआ है।' उन्होंने कहा कि छोटे चाय उत्पादक वार्षिक उत्पादन में भारी मात्रा में योगदान कर रहे हैं। रे ने कहा, 'घरेलू उपभोग में कुछ समय के लिए वृद्धि स्थिर बनी हुई है जबकि निर्यात में भी गिरावट आई है।' देश में चाय का उपभोग 2019 में 110.9 करोड़ किलोग्राम रहा, जो कि इससे पिछले साल 108.4 करोड़ किलोग्राम रहा था। अधिकारी ने कहा कि घरेलू उपभोग में सुस्त वृद्धि और निर्यात में कमी को देखते हुए जरूरत से ज्यादा चाय आपूर्ति की स्थिति से निपटने की आवश्यकता है। रे ने कहा, 'यदि हम अतिरिक्त उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए कदम नहीं उठाते हैं तो छोटे चाय उत्पादकों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा।'आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पारंपरिक तरीके से प्रसंस्कृत चाय किस्म का उत्पादन 2.85 करोड़ टन जबकि ब्लैक टी के प्रसंस्करण की विधि का उत्पादन 2.49 करोड़ टन बढ़ा। ग्रीन टी का उत्पादन 2019 में घटकर 24.2 लाख किलोग्राम रह गया। जनवरी-नवंबर 2019 के दौरान, चाय का निर्यात 22.7 करोड़ किलोग्राम रहा, जो कि एक साल पहले इसी अवधि में 23.13 करोड़ किलोग्राम रहा था।

प्याज के दाम में 40% गिरावट, मुंबई में सड़ रहा 7 हजार टन विदेशी प्याज

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

देश में प्याज की थोक कीमतों में पिछले एक हफ्ते में 40 फीसदी की गिरावट आ गई है। दूसरी तरफ, विदेश से आयात हुआ प्याज कोई लेने वाला नहीं दिख रहा और मुंबई के बंदरगाह पर 7 हजार टन आयातित प्याज सड़ रहा है।

क्यों किया गया था प्याज आयात

कुछ महीने पहले जब प्याज की कीमतें 150 रुपये की ऊंचाई पर पहुंच गई थीं तो सरकार ने विदेश से आयात का फैसला किया था। हालांकि, घरेलू बाजार में राहत मिलने के बाद आयातित प्याज सड़ने लगा है। एजेंसियों की खबरों के मुताबिक मुंबई के जेएनपीटी पर बाहर से आयातित 7 हजार टन प्याज सड़ रहा है। यह 45 रुपये प्रति किलो कीमत पर यह प्याज आयात किया गया है, जबकि थोक बाजार में कीमत 24 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है।

अब क्या है कीमत

देश की थोक मंडियों में मंगलवार को लगातार पांचवें दिन प्याज की कीमतों में गिरावट आई। एक हफ्ते में कीमत 40 फीसदी गिर गई है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित लासलगांव मंडी में मंगलवार को प्याज की कीमत 24 रुपये प्रति किलोग्राम थी। यह 20 जनवरी के 40 रुपये प्रति किलो रेट के हिसाब से करीब 40 फीसदी की गिरावट है। इसके पहले प्याज की यह कीमत 6 नवंबर को देखी

गई थी। इसकी वजह से खुदरा प्याज की कीमत 40 से 44 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। ऐसे में आयातक माल खाली करवाने की जल्दी में नहीं दिख रहे। मुंबई के जेएनपीटी पर एक महीने से 250 रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में रखा गया 7,000 टन इंपोर्टेड प्याज सड़ रहा है।

80 फीसदी आयातित प्याज सड़ने की आशंका

कुछ दिनों पहले उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने भी कहा था कि केंद्र सरकार राज्यों को 55 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज दे रही है। सरकार ने अब तक विदेशों से 24,500 टन प्याज मंगाया है, जबकि आयात के कुल 40,000 टन के सौदे हुए हैं। लेकिन राज्यों ने केवल 2,000 टन प्याज ही उठाया है, लिहाजा अब बचे हुए 89 फीसदी प्याज के सड़ने की चिंता बढ़ रही है। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकारें आयातित प्याज लेने से मना कर रही हैं।

क्यों घटी कीमत

पिछले दिनों नए प्याज की आवक मंडियों में बढ़ गई है जिसकी वजह से प्याज की कीमतों में गिरावट आई है। प्याज का दाम बढ़ने पर किसानों ने रबी सीजन में अच्छी फसल लगाई है और प्याज का रकबा चालू सीजन में 9.34 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल रबी सीजन में प्याज का रकबा 7.6 लाख हेक्टेयर था। मालूम हो कि बीते मॉनसून में हुई भारी बारिश से खरीफ सीजन में प्याज की फसल खराब होने से देश में प्याज की उपलब्धता कम हो गई थी, जिसके कारण प्याज के दाम आसमान छू गए थे. लिहाजा, केंद्र सरकार ने प्याज के दाम को काबू में रखने के लिए पिछले साल सितंबर में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

जिंस कारोबारियों की भारतीय बाजारों में कारोबार लागत कम करने का आग्रह

नयी दिल्ली। एजेंसी

जिंस बाजार प्रतिभागियों के शीर्ष संगठन कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंडिया (सीपीएआई) ने सरकार से भारतीय बाजार में कारोबार की ऊंची लागत को कम करने का आग्रह किया है। उसका कहना है कि ऊंची लागत के कारण सौदों में भारी कमी आई है। वित्त मंत्रालय को दिए प्रस्तुतीकरण में सीपीएआई ने कहा कि भारत में विभिन्न परिसंपत्तियों में लेनदेन की लागत अमेरिका, चीन और सिंगापुर में लेनदेन की लागत से चार से 19 गुना अधिक है। इसकी वजह प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) और जिंस लेनदेन कर (सीटीटी) का अधिक होना है। संगठन चाहता है कि सरकार एसटीटी और सीटीटी की दरों को घटाए या फिर पूरी तरह से हटा दे ताकि सौदों की संख्या और आकार को बढ़ाया जा सके। सीपीएआई ने कहा, 'कारोबार की अधिक लागत की वजह से सौदों की मात्रा में काफी कमी आई है। इससे पूंजी की स्थिति पर असर पड़ा है और शेयर के खरीद-फरोख्त करने पर आने वाली लागत बढ़ गई है।' संगठन ने सरकार से कहा है कि एसटीटी को व्यय मानने के बजाय पहले भुगतान किया गया रिफंड नहीं होने वाला कर मानना चाहिये या फिर आयकर की धारा 88 ई के तहत इसपर छूट दी जानी चाहिये जैसा कि 2008 तक व्यवस्था रखी गई थी। ऊंची कारोबार लागत के कारण जिंस कारोबार के सौदों में भारी कमी आई है। सीटीटी लागू होने के बाद 2013 से जिंस बाजारों में जहां 2011- 12 में 69,449 करोड़ रुपये प्रतिदिन के सौदे हो रहे थे वह 2018-19 में कम होकर 27,291 करोड़ रुपये प्रति दिन रह गये। इस प्रकार सौदों के मूल्य में 61 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। इस बीच, एचडीएफसी ने आम बजट से पहले रियल एस्टेट क्षेत्र की फंसी परियोजनाओं के लिए बैंक कर्ज के एक बार पुनर्गठन की वकालत की है। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा कि ऋणदाता परियोजनाओं के लिए नया कर्ज नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जिन इकाइयों के का ऋण पहले एनपीए हो चुका है उनका नया कर्ज पहले दिन ही एनपीए बन जाता है। पारेख की ओर से यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है रियल एस्टेट क्षेत्र संकट के दौर से गुजर रहा है और सरकार ने फंसी परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपये के कोष की घोषणा की है। पारेख ने संवाददाताओं को बताया, 'हमने राष्ट्रीय आवास बैंक और अन्य लोगों से प्रावधानों और परियोजनाओं के एनपीए के मुद्दों पर फिर से गौर करने का आग्रह किया है।' उन्होंने कहा, 'हम नियामकों से बातचीत कर रहे हैं, हमने वित्त मंत्रालय से बातचीत की है, ऋण का एकबार पुनर्गठन बहुत जरूरी है।'

Polymer MIS

Market Intelligence Source

In this information age having latest news, information, data and analysis is critical to the success of any business. We at PolymerMIS provide you exactly with this for Polymer and Petrochemical Industries, to help you have an edge over your competitors and stay ahead of them in every segment.

We bring to you on real time basis with breaking news as it happens, including market trends, quotes, moves, analysis, data, predictions and much more. We provide everything you need to know to stay informed and react to changing market conditions.

Advantages of Being with PolymerMIS

• Most important, its Economical. • Information on fingertips - SMS based alerts. • Quickest method of information delivery. • No hassle to browse to reach the content applicable for you. Pay for only what you need. • Covers Wide range of petrochemical products and feedstock including Aromatics, Olefins, crude oil, Polymers etc.

Sample SMS from PolymerMIS

Brent Crude Oil $48.83 US$/Rs.65.66 Propylene $605 CFR China Ethylene $1000 CFR NEA Naphtha $460 CFR Japan Styrene $920 CFR China.

PE market Updates - Intl. market assessed as firm amid short supply and higher Ethylene of 1005$ in SE Asia. November offers for India are above 1200$ for LL/HD/LD. Converters are keeping low inventories due to upcoming festivals and we may see revival of demand after 15th November.

RIL reduced PP Prices by Rs. 2000/MT and PP Random by Rs. 3000/MT Price Protection withdrawn w.e.f. 1 November 2015.

Various Plans we offer

We provide two broad categories of Plans for subscription:-

SMS Plan - In SMS Plan, we provide you SMS based alerts on Market Prices for Various Polymers and Daily Updates on Plants, Crude, Forex, Market Trend and Projections, Market Moves, Corporate Actions, Impact of Global changes etc.

Web Plan - PolymerMIS has emerged one of the Best Web Plan among thousands of our clients in India and across the world. Where our clients will get sms alerts and web access on our portal for Domestic and International Plastic Industry updates, Breaking News, Instant News alerts, Trend Analysis, Technical Analysis, Historic Data, Comparison of various Grades as well as Daily Newsletter, Latest News and Updates of HDPE, LDPE, LLDPE, PP, EVA, PVC, GPPS, HIPS, ABS, SAN and all Feedstock Prices and Market Trends on relevant subjects without cluttering your inbox. We bring whole Polymer industry under your thumb by providing our complimentary Android and ios Services. We want all our customers to have a fantastic experience with our latest news and updates. Our goal is to inform you before anyone else. We always effort to present you the best possible services every time. There's more to know about Polymer industry. Kindly visit at www.polymermis.com

VISTA WEBSOFT PRIVATE LIMITED

Corporate Office:
402 Morya Blue Moon,
B-57 off New Link Road,
Fortune Terrace Lane,
Andheri West, Mumbai -400053, India
Tel.: +91-22-26736570, Fax: +91-22-26736522,
Email: sales@polymermis.com

Branch Office :
2/12, South Tukoganj,
Near Noble Hospital,
Indore, M.P. 452001, India
Tel: +91-731-4068185, Fax: +91-731-4068185,
Email: sales@polymermis.com

Visit us at : www.polymermis.com

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।